



आदर्श कारागार अधिनियम, 2023

प्रलिस के लयः

[जेल अधनलनडड, 1894](#), [जेल](#), [राज्य का वषलड](#), [NCRB](#), [NALSA](#), [ई-जेल](#)

डेनूड के लयः

आदर्श कारागार अधनलनडड, 2023, डारत डें कारागार से संबंघतल डुदडे

करा डें करुं?

गृह डंतरालड (MHA) ने 'डॉडल जेल अधनलनडड, 2023' तैडार करलड है, जो डूरतलशल डुग के कानून (1894 का जेल अधनलनडड) की जगह लेगा, तलकजेल डूरशासन डें सुधार करलड जा सके, यह कैदडुं के सुधार और डुनरवास डर धडान केंदरतल करेगा ।

आदर्श कारागार अधनलनडड, 2023:

आवश्यकता:

- डुराने सुवतंतरता-डूरव अधनलनडड, 1894 के कारागार अधनलनडड डें "कई खलडडुं" हैं और डौजूदा अधनलनडड डें सुधारातडक डोकस की "सडषुट करूक" थल ।
- जेल अधनलनडड 1894 डुखड रूड से अपराधडुं को हरलसत डें रखने और जेलुं डें अनुशासन एवं वडवसुथा को लागू करने डर केंदरतल है । इस अधनलनडड डें कैदडुं के सुधार तथा डुनरवास का कोई डुरावधान नही है ।

नए अधनलनडड की डुखड वशलषताएँ:

- कारागारुं डें डुडलइल डुन जैसी डुरतडंधतल वसुतुओं के इसुतेडलल डर कैदडुं और कारागार करडडलरडुं के लडड डंड का डुरावधान ।
- उकरू सुरकूषा वाले कारागारुं, खुले कारागारुं (खुले एवं अरदुध खुले) की सुथाडना एवं डुरबंधन ।
- कुरुखुडत और आदतन अपराधडुं की आपराधकल गतवलधलडुं से सडलज को सुरकूषतल रखने के डुरावधान ।
- अकरू आकरण को डुरुुतसाहतल करने के लडड कैदडुं को कानूनी सहाडता, डैरुल, डरुलो और सडड से डुरलहे रहलई डुरदान करना ।
- कैदडुं का सुरकूषा डुलडुंकन और अलगाव, कसलसी वडकतु की सजुा का नरुधरण; शकलडत नवलरण, कारागार वकलस डुरुड, कैदडुं के डुरतल वडडवहार डें डदलाव एवं डुरललल कैदडुं, टुरांसजेंडर आदल के लडड अलग आवास का डुरावधान ।
- कारागार डुरशासन डें डारदरशतल लाने की दृषुटल से इसडें डुरुुदडुगकी के उडडुग का डुरावधान, नुडलडलरुु के साथ वीडडुु कौनडूरुसगल का डुरावधान, कारागारुं डें वैजुजानकल तथा तकनीकी हसुतकूषेड आदल का डुरावधान करलड गडल है ।

डहतुतव:

- डारत डें कारागार और 'उसडें हरलसत डें रखे गए वडकतु' राज्य का वषलड है । आदर्श कारागार अधनलनडड, 2023 का उडडुग राजुुु डुवलरल डुरतुडेक राज्य की सीडलओं के डुतर अडनलए जाने वाले आदर्श कानून के रूड डें करलड जा सकतल है ।
- कैदी अधनलनडड, 1900 और कैदडुं का सुथलनलंतरण अधनलनडड, 1950 दशकुु डुरलनल है तथा इन अधनलनडडुं के डुरलसंगकल डुरावधानुं को आदर्श कारागार अधनलनडड, 2023 डें शलडल करलड गडल है जसलसे डुरलरतीय कारागार डुरणलली को अंतरराषुटरीड डलनकुु के साथ संरुखतल करने और आवशुडक सुधार होने की उडडुड है ।

डारत डें कारागार से संबंघतल डुदडे:

कारागार डें कूषडता से अधकल डीड:

- यह डारत डें कारागार डुरणलली का गंडीर डुददा रहा है । [राषुटरीड अपराध रकलरुड डडुु](#) की एक रडुलरुट के अनुसलर, कारगारुं की अधडुग डर (Occupancy Rate) जेल कूषडता का 118.5% है ।
- यह डलडल गडल कल 4,03,700 की कूषडता वाले कारगारुं डें कैदडुं की संखुडल लगडग 4,78,600 थी ।
- डीडडलड के कारण रहने की सुथतल खलरलड हुुती है । इससे कई संकरलरी रुरुगुं के संकरण का जुरुखडल डनल रहतल है ।

सुवलसुथड और सुवकरूतल:

- बहुत से कारागारों में उचित चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इससे कई कैदियों की अनदेखी भी की जाती है और उनमें से अधिकांश अनुपचारित ही रहते हैं। कैदियों के लिये साफ-सफाई व स्वच्छता की भी व्यवस्था ठीक नहीं है।
- **ट्रायल में विलंब:**
 - ऐसा देखा जाता है कि कई मामले कई वर्षों से लंबित हैं। इससे जेल प्रशासन प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न होता है। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 मामला 1979 में कैदियों के त्वरित परीक्षण/ट्रायल के अधिकार को मान्यता दी।
- **हरिसत में यातना:**
 - कैदियों को हरिसत में यातनाएँ काफी प्रचलित हैं। हालाँकि वर्ष 1986 में डी.के. बसु के मामले में लिये गए ऐतिहासिक फैसले के बाद पुलिस को थर्ड-डिग्री यातना देने की अनुमति नहीं है, फरि भी जेलों के अंदर क्रूर हरिसा का प्रचलन है।
 - गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2017-2018 के दौरान पुलिस हरिसत में मौत के कुल 146 मामले दर्ज किये गए, पछिले पाँच वर्षों में हरिसत में मौत की सबसे अधिक संख्या (80) गुजरात में, इसके बाद महाराष्ट्र (76), उत्तर प्रदेश (41) में दर्ज की गई।
- **महिलाएँ और बच्चे:**
 - महिला अपराधियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। हालाँकि उन्हें स्वच्छता सुविधाओं की कमी, गर्भावस्था के दौरान देखभाल की कमी, शैक्षिक प्रशिक्षण की कमी सहित शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
 - बच्चों को ज़्यादातर जेलों के बजाय सुधार गृहों में रखा जाता है ताकि वे खुद को सुधार सकें और अपने सामान्य जीवन में वापस जा सकें। हालाँकि उन्हें बहुत अधिक दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है एवं मनोवैज्ञानिक आघात से गुज़रना पड़ता है।

इन समस्याओं पर नयितरण:

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में जेल सुधारों पर अपने सेवानवित न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की अध्यक्षता में एक समितिका गठन किया।
- भीड़भाड़ यानी स्पीडी ट्रायल, वकीलों से कैदियों के अनुपात में वृद्धि, विशेष न्यायालयों की शुरुआत, स्थगन से बचने की समस्या को दूर करने हेतु सफ़ारिशें की गईं।
- उन्होंने जेल के पहले सप्ताह में प्रत्येक नए कैदी हेतु निःशुल्क फोन कॉल की भी सफ़ारिश की। समिति ने आधुनिक रसोई सुविधाओं की भी सफ़ारिश की।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 304 हरिसत में मौत हेतु सज़ा का प्रावधान करती है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 में जेलों के अंदर CCTV लगाने के बारे में सफ़ारिश की है।

भारत में कारागार सुधारों से संबंधित पहलें:

कारागार योजना का आधुनिकीकरण: कारागारों, कैदियों और कर्मियों की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना वर्ष 2002-03 में शुरू की गई थी।

- **कारागार योजना का आधुनिकीकरण (2021-26):** सरकार ने नमिनलखिति के लिये कारागार में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने हेतु योजना के माध्यम से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है:
 - कारागारों की सुरक्षा बढ़ाई जाए।
 - प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से कैदियों के सुधार और पुनरवास के कार्य को सुगम बनाना।
- **ई-कारागार योजना:** ई-कारागार योजना का उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से जेल प्रबंधन में दक्षता लाना है।
- **मॉडल प्रज़िन मैनुअल 2016:** मैनुअल कारागार के कैदियों को उपलब्ध कानूनी सेवाओं (मुफ़्त सेवाओं सहित) के संदर्भ में वसितृत जानकारी प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA):** इसका गठन वधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था, जो 9 नवंबर, 1995 को समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ़्त और सक्षम वधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करने के लिये लागू हुआ था।

नषिकर्ष:

- भारत की कारागार प्रणाली में प्राचीन काल से महत्त्वपूर्ण सुधार हुए हैं लेकिन आधुनिक समय में अभी भी इसमें और सुधार की आवश्यकता है।
- भारत में लागू किये गए विभिन्न कारागार सुधारों के बावजूद स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि यद्यपि कैदियों ने अपराध किये हैं, फरि भी उनके पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उनसे छीने नहीं जा सकते।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

